(क) क्या सरकार को असम में विशेषकर अनुसूचित (जनजातीय) जिलों में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) की बढ़ती गतिविधियों की जानकारी है और यह कि वह अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए गरीब/जरूरतमंद लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम-सरकार ने राज्य के और अधिक जिलों को ‘उल्फा’ प्रभावित घोषित किये जाने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कौन-कौन से जिलों को ‘उल्फा’ प्रभावित घोषित किया गया है; और

(ङ) इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

**(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।**

**दिनांक 25.04.2012 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 293 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**(क) से (­­ङ) : इस समय युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) के साथ त्रिपक्षीय वार्ता चल रही है, जबकि परेश बरूआ के नेतृत्व वाला उल्फा का एक गुट अभी भी शांति वार्ता का विरोध कर रहा है । रिपोर्टों के अनुसार, उल्फा (वार्ता विरोध गुट) असम के कुछ भाग तथा अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और मेघालय के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सक्रिय है । तथापि, इस समय उल्फा (वार्ता-विरोधी) की गतिविधियां दो पर्वतीय जिलों नामत: कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ तथा अनुसूचित जनजातियों (एस टी) की आबादी वाले बोडोलैण्ड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट (बीटीएडी) में भी महत्वपूर्ण नहीं हैं । ऐसी कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है जिससे यह पता चले कि उल्फा द्वारा अपनी गतिविधियों के लिए इन जिलों के गरीब/जरूरतमंद लोगों को अपने जाल में फंसाया जा रहा है ।**

 **असम सरकार ने राज्य में उल्फा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करने की मांग नहीं की है । विगत तीन वर्षों के दौरान हिंसा की घटनाओं और हताहतों की संख्या में कमी के संदर्भ में असम में सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है । उल्फा (वार्ता विरोधी गुट) के विरुद्ध सुरक्षा बलों द्वारा समन्वित कार्रवाई जारी है ।**